और स्वैच्छिक संस्थाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इन संस्थाओं को प्रतिवर्ष दी जा रही वित्तीय और अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इनके कार्य का मूल्यांकन किया जा रहा है; यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) मध्य प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए 6 स्वैच्छिक एजेंसियों को अनुदान संस्वीकृत किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन्हें वर्षानुसार दी गई वित्तीय सहायता नीचे दी गई है:-

वर्ष	स्वैच्छिक एजेंसियों की संख्या	परियोजना का आकार	संस्वीकृत अनुदान
1987-88	1	600 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	19,20,000/-
1988-89	3	660 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	21,00,000/-
1989-90	3	663 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	22,62,160/-

(ग) जी हां, 1987-88 के दौरान संयुक्त मूल्यांकन दल जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार का एक-एक प्रतिनिधि तथा एक गैर-सरकारी सदस्य था, ने 1986-87 के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों के कार्य का मूल्यांकन किया। यह पाया गया था कि

(i) दो स्वैच्छिक एजेंसियों का कार्य संतोषजनक था;

(ii) एक स्वैच्छिक एजेंसी का कार्य संतोषजनक पाया गया था, परंतु उसमें सुधार की आवश्यकता थी;

(iii) दो स्वैच्छिक एजेंसियों का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया था क्योंकि एजेंसी बड़ी परियोजना कार्यान्वित करने में सक्षम नहीं थी;

(iv) एक स्वैच्छिक एजेंसी का कार्य असंतोषजनक पाया गया था;

(v) पांच स्वैच्छिक एजेंसियों का कार्य न केवल असंतोषजनक पाया गया था अपितु उनकी प्रमाणिकता पर भी शंका थी।

Setting up of regional offices of Administrative Staff College

145. SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Administrative Staff Colleges of India has recommended setting up of more regional offices;

(b) if so, where and by when these regional centres have been proposed to be set up; and

(c) what would be infrastructure of these centres?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Gadgil formula

146. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have dropped the idea of amending the